

दुआ करें, पसमांदा मुसलमानों को मिलेगा 8 प्रतिशत आरक्षण



रागेन्द्र स्वरूप सभागार सिविल लाइन में आयोजित सेमिनार में उपस्थित केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल एवं अतिथिगण। फोटो : एसएनबी

कानपुर (एसएनबी)। मदरसा जामे हिदाया का '21वीं सदी सामाजिक एवं आर्थिक चैलेंजेज' विषयक सेमिनार रविवार को सिविल लाइंस स्थित रागेन्द्र स्वरूप सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि पसमांदा मुसलमानों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण मिला है। बस दुआ करें, आगे 8 प्रतिशत तक आरक्षण जरूर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि भारत में हर मजहब के लोग रहते हैं। एक खानदान की तरह मिल जुलकर साथ रहते हैं। दुनिया में भारत सबसे कामयाब सेकुलर मुल्क की पहचान बना चुका है। जहां जमूहरियत की बात होती है तो अकसरियत व अकलियत की तस्वीर सामने आती है। अकसरियत का काम होता है देश में

करोड़ तक धन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका प्लान अभी हुकूमत के सामने है। अब अगले साल चुनाव का माहौल शुरू होगा। 40 हजार करोड़ का बजट दो साल के बाद बन सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को एनजीओ चलाने की

रागेन्द्र स्वरूप में मदरसा जामे हिदाया का '21वीं सदी: सामाजिक एवं आर्थिक चैलेंजेज' पर सेमिनार

घोषणा की है। मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। स्कालरशिप के मामले में अब छात्र-छात्राओं को हर वर्ष प्रमाणपत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। साथ ही एक बार

उन्होंने कहा कि सांसद निधि का पैसा अल्पसंख्यक, सिख, दलित आदि के उत्थान में खर्च हुआ है या नहीं, इसका हिसाब-किताब देखने को हर नागरिक को खुली छूट है क्योंकि सांसद आपके ही वोटों से बनता है। मदरसा जामे हिदाया के संचालक मौलाना फजलुर्रहीम मुजददी ने कहा कि 21वीं सदी का दौर तकनीकी है। इसमें वही कौम तरक्की करेगी, जो अपने को समय के अनुसार सांचे में ढाल सकेगी। हमारी कौम की शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक हिस्सेदारी का विशेष ध्यान भारत सरकार ने अपनी योजना में नहीं रखा है। अगर हमारी कौम ने अपने हक व अख्तियार को नहीं समझा और नाइंसाफी के खिलाफ जमहूरी तरीके से एकजट होकर जददोजहद नहीं की तो

आती है। अकसरियत का काम होता है देश में निजाम बनाना लेकिन अकलियत इतनी दबा दी जाती है और रौंद दी जाती है, तब जमूहरियत नहीं रह जाती है। उन्होंने कहा कि मदरसा जामे हिदाया के संचालक मौलाना फज़लुर्रहीम मुजददी ने सरकार से मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए 50 हजार करोड़ की मांग की थी। उनकी मांग के अनुसार 40 हजार

प्रमाणपत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। साथ ही एक बार बनवाये गये प्रमाणपत्र का साल में रिन्यूवल भी नहीं कराना पड़ेगा। केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि भारत तभी महाशक्ति बन सकता है, जब अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेंगे। भारत के 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। अब 21वीं सदी में देश दाखिल हो चुका है।

तरीके से एकजुट होकर जद्दोजहद नहीं की तो हम पिछड़ जाएंगे। मोमिन कांफ्रेंस के महामंत्री अख्तर हुसैन अख्तर ने कहा कि सेमिनार के बाद नवयुवकों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इस मौके पर जहीरउद्दीन खान, आजम खान, डा. जमील अहमद, शुएब अहसर, एसएम हिलाल आदि थे।